[SHRI VAYALAR RAVI]

want to return to India, the Embassy would do everything to send them back. There is no problem, Sir, we can take them back. But a majority of them do not want to come back. This is the situation, and the Embassy is monitoring the situation, discussing with the workers, discussing with the Indians who are managing the cement factory. And, Sir, though it is 450 kms. away from the capital, yet, one of our Counsellors went and stayed there. And, I can assure, Sir, that we will continue to do that and see to it that the interests and welfare of the workers are protected. We will do that.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Now we will take up ...(*Interruptions*)...

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब) : सर, मैं यह कहना चाहता हूँ ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : No; it was just an intervention in response to the demand of some hon. Members. Now, we shall take up the North-Eastern Areas (Reorganisation and Other Related Laws (Amendment) Bill, 2012.

GOVERNMENT BILLS – *Contd.*

The North-Eastern areas (Reorganisation and Other Related Laws (Amendment) Bill, 2012

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) : Sir, I move:

> "That the Bill further to amend the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and Other Related Laws, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

This Bill has been brought with an object of setting up separate High Courts in the States of Manipur, Meghalaya and Tripura. Sir, as you are aware, the Guwahati High Court was a common High Court. This was a long-felt demand and aspiration of the people of Manipur, Meghalaya and Tripura. It could not be done so far because the High Court buildings were not ready and the infrastructure was not ready. Now the buildings are ready, and therefore, it is time that we fulfilled our promise and created separate High Courts for Manipur, Meghalaya and Tripura. The Bill seeks to achieve that objective. I would request all sections of the House to support the Bill.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Shri Tarun Vijay. Not present. Shri Bhubaneswar Kalita.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam) : Sir, I am told that the other House had passed this Bill without discussion. Since there is unanimity in the House that this Bill should be passed without discussion, I support that.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR) in the Chair]

But I would just want to draw the attention of the Minister to three short points. One is the pendency of cases in the Courts which is very high. We have to find out ways and means to reduce it. The second is the ratio of judge and population which is very high in this country, and especially, in the North-Eastern Region. This should be reduced. And my third point is this. We have been making an appeal, since very long, for the setting up of a Bench of the Supreme Court at Guwahati. Now that three High Courts have been set up in the North East, the number of cases in the Guwahati High Court will be more. So, as I have appealed earlier, a Bench of the Supreme Court should be set up at Guwahati. Thank you, Sir.

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में उच्च न्यायालय स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया है, यह इन तीनों क्षेत्रों की बहुत पुरानी माँग रही है और इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। यह बिल पूर्वांचल के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत देगा जिनको अपने सामान्य मामलों के लिए बार-बार गुवाहाटी जाना पड़ता था और उस क्षेत्र में पहले से ही पनप रहे अनेक मुद्दों पर जो असन्तोष के विषय हैं, उन असन्तोष के विषयों को बढ़ाने में वह समस्या एक मददगार होती थी।

महोदय, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ये भारत के सबसे सुन्दर प्रदेशों में माने जाते हैं, लेकिन यह विडम्बना है कि इस देश में जो सबसे सुन्दर प्रदेश हैं, चाहे वह कश्मीर हो या मणिपुर, वे अराजक विद्रोही गतिविधियों, भारत-विरोधी आतंकवाद आदि समस्याओं से ग्रस्त होकर बाकी देश में एक विडम्बनापूर्ण स्थिति पैदा करते हैं। मणिपुर के गोविन्द जी मंदिर, मणिपुर की मितेह और वैष्णव परम्पराएँ, वहाँ के नृत्य, वहाँ की झीलें और वहाँ के जंगल पूरे विश्व में एक अनूठी आभा और प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध हैं। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। मणिपुर में सम्भवत: पूर्वांचल के सबसे बड़े आतंकवादी और अराजक संगठन भी कार्य कर रहे हैं, इस कारण वहाँ सामान्यत: प्रशासनित ढाँचा बड़ा बिखरा हुआ-सा रहता है। वहाँ कभी 50 दिनों की हड़ताल होती है, तो कभी 66 दिनों का बन्द होता है और उसमें वहाँ का प्रशासन ही नहीं, बल्कि तमाम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। वहाँ पर गैस के सिलेण्डर 1200 रुपये में मिलते हैं, स्कूल बन्द रहते हैं, गाँवों में आना-जाना बन्द हो जाता है। ऐसी स्थिति में, गृह मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है, उसमें मणिपुर से ही आठ से अधिक ऐसे संगठन हैं, जो प्रतिबन्धित किये गये हैं, जिनमें से एक संगठन का नाम People's Liberation Army है। यह सभी जानते हैं कि People's Liberation Army हमारे पड़ोसी देश की सेना का नाम है और वह गृह मंत्रालय द्वारा मणिपुर में प्रतिबन्धित एक आतंकवादी विद्रोही संगठन है। महोदय, मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि ये उच्च न्यायालय जो वहाँ स्थातिप किये जा रहे हैं, ये वहाँ की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने में मददगार साबित होने वाले हैं। जब वहाँ के लोगों को और वहाँ के वकीलों को अपनी सामान्य क़ानूनी आवश्यकताओं के लिए सैंकड़ों मील दूर गुवाहाटी आना पड़ता था, तो उनको वहाँ न केवल रुकने की समस्या होती थी, बल्कि उनके लिए वहाँ परिचय की भी दिक्कत होती थी। जब आतंकवादी विद्रोही गतिविधियों के कारण इन क्षेत्रों में गुवाहाटी तक के तमाम राजमार्ग बन्द कर दिए जाते हैं, जो उनकी प्राणवाहिनी है, उनकी life-line है, तब उस कारण से विशेष रूप से मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के क्षेत्रों

[श्री तरुण विजय]

को जो बेहद कठिनाई होती है, उस कठिनाई का सामाधान ये उच्च न्यायालय बनने के कारण होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है।

महोदय, इस अवसर पर मैं यह भी बताना चाहूँगा कि मणिपुर न केवल अपनी वैष्णव परम्परा के कारण विख्यात रहा है, बल्कि मणिपुर और नागालैण्ड को जोड़ने वाली एक और विख्यात विभूति का, जिनका क़ानून के क्षेत्र में बहुत नाम रहा, वह Rani Gaidinliu थीं। वह 16 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ीं और अंग्रेजों ने तमाम क़ानूनों को धता बताते हुए उनको आजीवन कारावास का दण्ड दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस 16 साल की गुरिल्ला योद्धा Gaidinliu से मिलने कोहिमा की जेल गये और उन्होंने अपनी जीवन-कथा में लिखा है, "She was so majestic and royal in her looks that instantly I called her a Rani."

वह सामान्य देशभक्त योद्धा थी। लेकिन जब से पंडित जवाहर लाल नेहरू ने Gaidinliu के लिए रानी शब्द का उपयोग किया, तब से उन्हें रानी Gaidinliu कहा जाने लगा। वे मणिपुर में पैदा हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको ताम्र पत्र और पद्म विभूषण देकर नवाजा था। यह जो परिस्थिति रही कानून के उल्लंघन की, कानून के अज्ञान की, इस परिस्थिति के कारण भी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा असर पड़ा। ये जो उच्च न्यायालय बनेंगे, इन उच्च न्यायालयों की वजह से वहां के आर्थिक सुधारों को भी बहुत बड़ा सहारा और सिम्बल मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अरुणाचल प्रदेश के लिए भी इसी प्रकार से उच्च न्यायालय बनाया जाएगा, जहां लोगों को सैंकड़ों मील चलकर कठिनाइयों का सामना करते हुए गोहाटी तक आना पड़ता है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का एक बिल आई.ए.एस. कैडर को भी पृथक् करने के लिए विचाराधीन है। मेघालय को असम के साथ जोड़ा गया है लेकिन मणिपुर और त्रिपुरा की एक संयुक्त आई.ए.एस. सेवा है। उनकी 2004 से मांग है कि उनको भी आई.ए.एस. कैडर को पृथक् किया जाए। ये जो पूर्वांचल के क्षेत्र हैं, ये अपनी छोटी-छोटी मांगों के लिए वर्षों से दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहने के लिए मजबूर होते हैं। दस साल, पंद्रह साल तक इनकी छोटी-छोटी डिमांड्स पर विचार होता रहता है और उस पर फैसले नहीं किए जाते हैं। हाईकोर्ट की भी बिल्डिग बन गई हैं लेकिन उसमें जो आवश्यक सामान है वह अभी तक लाया जाना बाकी है। वे लोग पूछते हैं कि हमारी जो एक सामान्य मांग है, उसके लिए दिल्ली का दरबार दस-दस, बीस-बीस साल तक हमको क्यों प्रतिक्षा करवाता है। उनकी छोटी-सी ऐसी मांगें होती हैं कि कहीं उच्च न्यायालय हो, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कहीं पर सैनिक स्कूल खोले जाएं और इसके अलावा बाकी देश के प्रदेशों के अनुसार उनके आई.ए.एस. के कैडर भी अलग-अलग रखे जाएं। लेकिन जब उनकी ये सामान्य मांगें भी नहीं मानी जाती हैं तो इन कारण वहां एक विद्रोह और गुस्सा पैदा होता है।

महोदय, इस अवसर पर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पूर्वांचल में जो नागालैंड की स्थिति है, वहां पर गृह मंत्रालय की ओर से एक संदेश गया है, जिसमें कहा गया है कि Supra state likely for Nagaland. यह एक बहुत खतरनाक संदेश पूर्वांचल के क्षेत्रों को जाता है। आप मणिपुर में उच्च न्यायालय खोल रहे हैं। मणिपुर को सबसे ज्यादा डर अगर किसी चीज का है, तो वह नागालैंड की योजना से है। नागालैंड की योजना के अन्तर्गत वहां बृहत्तर नागालैंड में अरुणाचल, मणिपुर और मेघालय के अनेक तथाकथित नागा बाहुल्य क्षेत्रों को नागालैंड में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों जब मणिपुर में चुनाव हुए, तो नागालैंड के विद्रोही नेता और वहां के शासकीय नेता जब मणिपुर के नागा बाहुल्य क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए भाषण देने के लिए गए थे तो उनका कड़ा विरोध किया गया। यह विरोध इसलिए किया गया, क्योंकि मणिपुर को लगता है कि सम्भवत गृह मंत्रालय किसी दबाव में आकर मणिपुर के उन क्षेत्रों को, जहां नागा क्षेत्र के विद्रोही संगठन यह दावा करते हैं कि ये नागालिम के अन्तर्गत आने चाहिए,.....। वे क्षेत्र मणिपुर से काटकर नागालिम में

शामिल न कर दिए जाएं, इस भय का भी निस्तारण किया जाना चाहिए। अच्छी बात है कि आप वहां उच्च न्यायालय स्थापित कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वहां कम-से-कम ऐसे विवाद हों, जिन्हें अदालत की शरण लेनी पड़े और अधिकांश विवाद वे स्वयं ही हल कर लें। अब उच्च न्यायालय के साथ ही वहां एक और मांग शुरू हो गयी है और कोई भी क्षेत्र जो नागालिम के अंतर्गत आता है, चर्च वहां के अराजक और विद्रोही संगठनों को खुले आम समर्थन देता है और जब इन नागा विद्रोही संगठनों से बातचीत होती है, तो भी उसमें चर्च की भूमिका रहती है। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि आप उच्च न्यायालय तो वहां स्थापित कर दें, लेकिन इसके साथ ही इन नागा क्षेत्रों को मणिपुर से अलग न करने के लिए एक नया आंदोलन शुरू हो जाए? मैं इस अवसर पर यही अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर पूर्वांचल देश का मुकुट मणि क्षेत्र है। अभी मैंने बताया कि प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने इस पूरे उत्तर पूर्वांचल को यक्ष प्रदेश कहा था, रुक्मणी का क्षेत्र कहा, कृष्ण का प्रदेश कहा था। अरुणाचल में भीष्मक नगर प्राचीन यादव संस्कृति का एक असाधारण, अनूठा नमूना है, जहां कृष्ण और रुक्मणी की गाथाएं आज भी गायी जाती हैं। वहां परशुराम कुंड है। मणिपुर का क्षेत्र, मणि-कांचन का क्षेत्र माना जाता है, जहां गए बिना भारत की संस्कृति को समझना कठिन होता है। ऐसे क्षेत्र को अराजकता व आतंकवाद से भी गृह मंत्री जी मुक्ति दिलाएं। वे लोग आप से यही अपेक्षा करते हैं कि वहां भारत और भारतीयता के विरुद्ध जो विद्रोह का वातावरण है, वह जल्दी-से-जल्दी समाप्त हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 15 वर्षों से मणिपुर में हिंदी प्रतिबंधित है। वहां हिंदी फिल्में नहीं दिखायी जा सकतीं। वहां लोग केवल दक्षिण कोरिया की फिल्में देख पाते हैं। वहां हिंदी पढ़ायी नहीं जा सकती, वहां पाठ्य पुस्तकों के अंत में जहां राष्ट्र गीत होता है, उसे वहां से हटा दिया गया है। वहां के विश्व-विद्यालयों में जो भारत के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनकी आवाज गूंजती है। वहां गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, सुरक्षा सैनिकों के संरक्षण में ही मनाया जा सकता है। महोदय, सामान्य तौर पर वहां के विद्यालयों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाने के उत्सव बड़ी कठिनाई से होते हैं। मैं वहां जाकर उन लोगों से मिला हूं। वे केवल एक ही बात कहते हैं कि मणिपुर देशभक्त प्रदेश है और मणिपुर भारत से केवल एक ही आशा रखता है कि वह हमारे दुःख में संवेदना रखे और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। वहां जब लगातार 200 दिनों तक राजमार्ग रोके जाने के आंदोलन होते हैं, जो दिल्ली के लोग कल्पना नहीं कर सकते कि उनको कितनी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है। वहां चिकित्सालय बंद, स्कूल बंद, दफ्तर बंद, बाजार बंद, गैस के सिलिंडर नहीं, किरोसिन नहीं, उसके बावजूद लोग 200 दिनों की हड़ताल भुगतकर भी तिरंगे के प्रति वफादार रहते हैं।

ऐसे प्रदेश को जिसे विशेषाधिकार और अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, हम तमाम अराजक, आतंकवादी और विद्रोह संगठनों के हवाले छोड़ देते हैं जो अपने पड़ोसी देशों की फौजों के नाम पर अपने विद्रोही संगठनों के नाम रखते हैं जब कि वहां के लोग केवल शांति चाहते हैं। ऐसे क्षेत्र के साथ जहां आप मेघालय व त्रिपुरा में भी उच्च न्यायालय स्थापित कर रहे हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं और समझता हूं कि ये उच्च न्यायालय उस क्षेत्र की मांग पूरा करने में समर्थ होंगे। साथ ही वहां शांति और एकता की भी बात सरकार करे, तो यह अधिक सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम्।

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura) : Sir, I would like to thank the hon. Home Minister for bringing forward this Bill. According to me, this is a non-controversial Bill, and I hope the entire House will support it. This has been a long-pending demand of the people of Tripura, who have been fighting for the establishment of a separate High Court for more than 25 years. The long-standing aspirations of the people of Tripura, Manipur and Meghalaya will be fulfilled through the passage of this Bill. Article 214 of our Constitution says, "There shall be a High Court for each State."

[SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA]

Sir, under the above mandate of the Constitution, some of the States, though smaller in size and population, have been provided with the Separate High Court. Tripura was a princely State till its integration with India by the merger agreement dated 15th September, 1949. Thereafter, until attainment of the Statehood on 21st January 1972, it had a permanent court of Judicial Commissioner, equivalent to the status of the High Court for dispensation of justice. This long tradition of an independent High Court in the State got discontinued only after Tripura obtained Statehood and it was brought under the Jurisdiction of the Gawahati High Court under the North-Eastern States (Re-organisation) Act, 1971. It is difficult for one High Court to faithfully and effectively discharge this Constitutional obligation on exercising effective control over subordinate Judiciary which is impossible. The Tripura Legislative Assembly passed a Resolution on 20th March, 1987, requesting the Central Government to take steps for establishment of a separate High Court for Tripura. A delegation of representatives of Tripura High Court Bar Association met the Prime Minister on 10th September, 2008 and ventilated the demand of a separate High Court for Tripura.

The Members of Parliament of Tripura also met the Union Law Minister several times and demanded early decision of the Government of India on this issue. The Chief Minister of Tripura also wrote several letters to the Union Law Minister in this connection. In spite of many communications from the State in this regard, the decision to set up a full-fledged High Court was delayed. I firmly believe that this Bill will open the window for establishment of separate High Courts for Tripura, Manipur and Meghalaya. In this connection, I would like to say that all the North-Eastern States should have a separate High Court. The people of this region have been fighting continuously for long to establish their constitutional rights.

So, I urge upon the Government to extend adequate help in a time-bound manner on top priority basis for all round development of the North-East.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal) : Sir, I am happy that after the enactment of the Indian High Courts Act, 1861, in the British Parliament, in pursuance whereof the Calcutta High Court, the Bombay High Court and the Madras High Court were established. After 150 years, the Central Government has decided to establish three High Courts at a time in Meghalaya, Manipur and Tripura. I fully support this stand of the Government of India because it is a welcome development that Government of India is trying to expand its justice rendering system even to the remotest areas of the North-East.

Although I would like to suggest only one or two points which may not be related to the hon. Home Minister and his Ministry, through you, Sir, I would request the hon. Home Minister to take up the matter with the Government of India that so many

vacancies of judges prevailing in this country in different High Courts are filled up. The Law Minister was here a few minutes back, he is not here now. I would request the hon. Home Minister—he is a very important Minister of this Government—to consider filling up those vacancies. Opening up of new High Courts is a welcome development. But, at the same time, it is very much required that the unfilled vacancies of judges are filled up so that there is a speedy disposal of pending cases.

So far as my State is concerned, I cannot but mention one fact, that there is a long-standing demand; the way, the long-standing demand of Meghalaya, Manipur and Tripura has been met by this amending Bill, in the same fashion, this demand should be met. Although the Government of India has decided long back to open a Circuit Bench of Calcutta High Court in North Bengal, *i.e.*, in Jalpaiguri, the State Government has provided land and infrastructure. But for the indifferent attitude taken by a section of the Judiciary, that Circuit Bench has not yet come up, which is detrimental to the interest of the people of North Bengal as a whole. Sir, I join the voice of Shri Bhubaneswar Kalita that a Circuit Bench should be set up, both at the Calcutta High Court and at the Guwahati High Court, so that litigants from these States won't have to come to Delhi very often to defend or file a case in the Supreme Court, which is very costly nowadays. I request the Government to consider it. Although it is not related to this amending Bill, I am sorry to say, but, perhaps, it is very important to look into it. Thank you, Sir.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (Tamil Nadu) : Sir, I rise to support this Bill. I appreciate the Government's intervention in ensuing establishment of mechanisms for justice in Tripura, Meghalaya and Manipur. According to the North-Eastern Areas (Re-organization) Act, 1971, a common High Court was established for five North-Eastern States, namely, Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya and Tripura, and the two erstwhile Union Territories, which are now full-fledged States, namely, Mizoram and Arunachal Pradesh. It was called the 'Guwahati High Court'.

Under the same Act, the North-Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971, Tripura, Manipur and Meghalaya became full-fledged States as on 21st January, 1972.

Sir, currently, the six North-Eastern States, except Sikkim, have the Guwahati High Court, and Sikkim has a separate High Court. Sir, Tripura alone has over 52,000 cases pending in different lower courts. Five thousand cases are awaiting disposal in the Agartala Bench of the Guwahati High Court. The requisite infrastructure is ready for the functioning of a full-fledged High Court.

Sir, this Bill addresses the aspirations of the people of Manipur, Meghalaya and Tripura by providing them easy, speedy and cost-effective access to justice. The establishment of separate High Courts, Sir, would definitely help in meeting the demand

[SHRIMATI VASANTHI STANLEY]

of the disposal of cases in a speedy manner, saving litigants' time and money and fulfilling a long-standing demand of these States.

Sir, this Bill paves the way for creation of full-fledged High Courts in these three States. A decade old demand of these people is being fulfilled through this Bill.

Sir, here, I would like to bring to the notice of the hon. Minister the number of pending cases in the Supreme Court and the High Courts. As on 1st March, 2012, approximately, 59,000 cases are pending in the Supreme Court; out of these, 20,470 cases have been pending for less than a year. As on 30th June, 2011, a total of 43 lakh cases were pending in the High Courts across the country, and 2.8 crore cases were pending in the district and subordinate courts. Approximately, nine per cent of these cases have been pending over ten years and a further 24 per cent cases have been pending for more than five years. So, this is another disturbing factor. When these many cases are pending, a large number of vacancies in the Judiciary are also there. As of March 20, 2012, there are 269 vacant judges' posts in the different State High Courts across the country, and 3634 vacancies in the district and subordinate courts, as of June 30, 2011.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR) : Thank you.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY : Sir, I will finish in just one minute. Sir, though it doesn't directly relate to this Bill, I would like to appeal to the hon. Minister about our long-pending demand for establishment of a Supreme Court Bench—as my other colleague was mentioning here about Calcutta—at Chennai and Mumbai. It will be a Charter Court, of course.

Sir, this issue also doesn't come directly under you, but there is a move that the Centre for Legal Studies and Research is about to be moved from Chennai.

I hope that you will give your full support so that the Centre for Legal Studies and Research would come to Chennai. Please put in your full efforts for this, Sir. Then, every State, as in the US, should have its own High Court and also the Supreme Court. If it is not possible, like Malaysia, Pakistan and Australia, courts of appeal can be established to avoid rush to the Supreme Court. This will save time, money and energy of the people. Thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill.

श्री राम कृपाल यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस बिल के माध्यम से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों की जनता की जो भावनाएं थी और लगभग पच्चीस वर्षों से जो मांग की जा रही थी कि वहां एक पृथक् उच्च न्यायालय बनाया जाए, उन भावनाओं के अनुरूप आपने इन राज्यों में उच्च न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो एक बहुत अच्छा कदम है।

महोदय, अभी तक उच्च न्यायालय गुवाहाटी में था और मैं समझता हूं कि अभी कई राज्यों की यह समस्या है। नॉर्थ-ईस्ट में असम को मिलाकर जो सात राज्य हैं, वहां की अवाम को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, यह समझा जा सकता है। कितने किलोमीटर दूर से लोग आते-जाते होंगे और उनको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। सरकार को यह काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, ताकि वहां के अवाम की जो समस्या थी, उसका निदान निकल पाता।

महोदय, वहां के सातों राज्यों में कई तरह की समस्याएं हैं। इन तीन राज्यों में आप उच्च न्यायालय का गठन ज़रूर कर रहे हैं और उससे उन लोगों को राहत मिलेगी, मगर जो स्थानीय समस्याएं हैं, उनकी तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, ताकि उन समस्याओं के प्रति सरकार सकारात्मक रुख अख्तियार करे और जो बेसिक समस्या है, जिसकी वजह से जगह-जगह पर आंदोलन होते रहते हैं, कहीं न कहीं उग्रवाद की घटनाएं भी होती रहती हैं, तो अगर उनको आप संतुष्ट करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह वहां के राज्यों के लिए, खास तौर पर मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लिए एक बड़ा कदम होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब देते समय यह ज़रूर बताएं कि वे उच्च न्यायालय तो खोल रहे हैं, मगर ये functional कब होंगे? इनको आप शक्ति तो प्रदत्त कर रहे हैं, लेकिन ये न्यायालय कब चालू होंगे? मैं समझता हूं कि अभी न्यायालय प्रारंभ होने की स्थिति में नहीं हैं। केवल buildings के बन जाने से काम नहीं चलेगा। जब आप जवाब दें, तो यह ensure करें कि न्यायालय पूरे तौर पर अपना कार्य कब प्रारंभ करेंगे, ताकि वहां की जनता की जो समस्या है, खास तौर पर मुकदमे से जुड़े जो मामले हैं, उनसे लोगों को निजात मिल सके और फिर वहां के लोग गुवाहाटी न जाएं।

महोदय, अंत में मेरा एक निवेदन और है और निश्चित तौर पर कई सदस्यों ने इस बात को रखा कि देश के विभिन्न न्यायालयों में बहुत सारे मुकदमे लम्बित पड़े हुए हैं। हम जिस प्रदेश से आते हैं, वहां भी और पूरे देश में अदालतों में बहुत सारे मुकदमे लम्बित हैं, जो उनके निदान के लिए कोई ठोस स्टेप सरकार को उठाना चाहिए, खास तौर पर जो न्यायाधीशों की कमी है, उसको पूरा करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए।

महोदय, मुझे विश्वास है कि यह जो बिल आज आया है, इसके माध्यम से काम बनेगा। आपने निर्णय ले लिया है कि अलग-अलग उच्च न्यायालय बनाए जाएं, तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के जो लोग थे, उनको गुवाहाटी आने-जाने से छुटकारा मिलेगा, लेकिन पूरे तौर पर छुटकारा कब मिलेगा और कब ये न्यायालय functional हो जाएंगे, आप अपने जवाब में यह ज़रूर बताएं। महोदय, सरकार ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है और वहां के लोगों की भावनाओं के अनुरूप कार्य किया है, इसलिए मैं पुन: इस बिल का समर्थन करता हूं और सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI SHANTARAM NAIK (Goa) : Sir, I rise to support The North Eastern Areas (Reorganisation) and Other Related Laws (Amendment) Bill, 2012. The Constitution provides, basically, that 'there shall be a High Court for each State'. This is the basic and fundamental provision which gives the right to every State to have a High Court. The other one is article 231, which is exceptional in nature and which says, "Notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this Chapter, Parliament may by law establish a common High Court for two or more States." This is a sort of an exception. But the fundamental article says that 'there shall be a High Court for each State'; and, therefore, I would like to ask: हमने क्या पाप किया? Why Goa was not included in this?

[SHRI SHANTARAM NAIK]

Just in short, I would tell you about the history of the Goa High Court. Just before the advent of the Portuguese in India, Goa was ruled by Adil Shah, the Sultan of Bijapur. He was the head of the Sultanate Judicial System, which had, at its top, a Qazi and below the Qazi there were Judicial Magistrates such as Wazirs and Amirs, vested with original and appellate powers within their territorial jurisdictions. There were also subordinate Judicial Officers. The Portugese, in the beginning, did not alter the judicial system, which was in vogue at the time of their conquest of Goa, but, gradually, they went on to introduce their own judicial system. Finally, in the year 1544, a High Court was created and was designated as *Tribunal de Relacao das Indias.* The said High Court was headed by a Chancellor and had three sitting Judges. In the year 1774, the then Portuguese Prime Minister abolished the *Tribunal de Relacao das Indias* and re-introduced the Office of Auditor General with all the powers of the High Court. The *Tribunal de Relacao das Indias,* that is, the High Court, was, however, re-established in 1776 and a Chancellor was to preside over the said Court with a Bench of five Judges. This situation continued to be in force, with slight changes, up to the time of the liberation of Goa, when a High Court, the *Tribunal de Relacao das Indias,* was functioning in this territory with five Judges and had its territorial jurisdiction extending up to the territory of Goa, Daman & Diu as well as the Portuguese colonies of Macau and Timor. That is, we had a High Court in Goa with its jurisdiction extending not only to Goa, Daman & Diu but Macau and Timor as well. We had such a powerful High Court before liberation. And, ultimately, what was given to us? It was a Judicial Commissioner's Court. The Judicial Commissioner's Court was, in fact, like a High Court. In fact, I had appeared before it in my early days, because there was a Weekly Board; this was the system then. From the District Court we used to appear in that Court. But, subsequently, when we demanded a High Court for Goa, we were not given a High Court, but we were given a Bench of the Bombay High Court, which Bench is now functioning. Now, if Meghalaya gets a High Court, Manipur gets a High Court and Tripura gets a High Court, why can't a place like Goa, with all its history get one? Does any other State have such a history? The Ministry could say that the Assembly has not passed a Resolution to that effect. In the Assembly, we don't take interest in it these days because we feel that we would not be given that. Nobody is bothered about the small States. We haven't got our own cadre. We don't get anything that we ask for and, therefore, we have not bothered to ask for it. All of a sudden, this Bill has come up. Somebody should have asked us whether a High Court is needed in Goa; Manipur, Meghalaya and Tripura are going to get it. But we were not asked. That is our grievance. We feel bad that we have not been considered in this regard.

Then, Sir, comes the question of the jurisdiction of the High Courts established in law. Article 214 says that laws declared by the Supreme Court shall be binding on

all Courts within the territory of India. Now, the question is, the Constitution contains an article which says that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts in India. So far, we felt that we were the only body which legislated, but, nowadays, it is very clear that there is another parallel body which legislates. In all humility, I would like to submit that this article needs to be re-defined.

Otherwise, there are two bodies which legislate. Therefore, under Article 214, we get so many legislations day in and day out, and we are neutralized. I am taking this opportunity right now on this Bill, and, that is why, I am making this small submission. This aspect should also be looked into. I again request the Home Ministry to please consult the Government of Goa and ask them whether they require the High Court, and please provide a High Court to Goa at the earliest.

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बिल देश की न्यायिक प्रक्रिया के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्यनीय डा. भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस बात की हिमायत की थी कि भारतवर्ष के अंदर छोटे राज्य और छोटे जिलों की स्थापना से, हम जहां विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने में सफलता अर्जित कर सकते हैं, वहीं पर न्याय की दृष्टि से सस्ते और सुलभ न्याय की परिकल्पना को भी पूरा किया जा सकता है। हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश विशाल आबादी और क्षेत्रफल में बंटे हुए हैं, जिसके कारण सस्ते और सुलभ न्याय की परिभाषा को पूरा किया जाना भारतीय लोकतंत्र में संभव नहीं हो सका है। इसका नमूना मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज की तारीख तक लोअर कोर्ट में 2.7 करोड़ केसेज़ पेंडिंग हैं, जिनका डिसिज़न नहीं हो पाया और 21 उच्च न्यायालयों में 42 लाख केस पेंडिंग हैं, जिनकी सुनवाई का मौका नहीं मिल सका। हमारा देश ग्रामीण अंचल में बसने वाला देश है। छोटी आमदनी, छोटी पूंजीवाले लोग बहुतायत में हमारे देश में रहते हैं। इन परिस्थितियों में, जब करोड़ों केसेज़ लोअर कोर्ट में पेंडिंग हों और 42 लाख केस उच्च न्यायालयों में पेंडिंग हों, तो ऐसे परिदृश्य में सस्ते और और सुलभ न्याय की परिकल्पना पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस बात का अनुरोध करूंगा कि जिन तीन राज्यों में आपने उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए आज जो बिल प्रस्तुत किया है, इस पर तो सदन अपनी सहमति आपके साथ व्यक्त करेगा ही, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इनके अलावा भी, आप देश के बाकी प्रदेशों की स्थिति, जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए, उस पर कोई रिव्यु कमेटी बनायें और इस बात पर विचार-विमर्श होना चाहिए कि किन-किन प्रदेशों में आबादी की दृष्टि से आज भी न्याय सभी घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर सरकार सम्पूर्ण भारत के लोगों को न्याय दिलाने की दृष्टि से देश के प्रदेशों का रिव्यु करके, इस तरह की बेंचिज़ और स्थापित करने की कोशिश करेगी, तो निसंदेह न्याय आम आदमी तक पहुंच सकेगा।

माननीय मंत्री जी, जहां तक मेरा संज्ञान है लोअर कोर्ट्स में एस.सी/एस.टी. के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। चूंकि यह मामला न्याय से जुड़ा है और देश के 85 फीसदी लोग ऐसे हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, कमजोर हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, किसान हैं, इनको अनेकों बार विषम परिस्थितियों की वजह से न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि जहां हमें सस्ते और सुलभ न्याय के लिए अधिक से अधिक उच्च न्यायालय स्थापित करने की आवश्यकता है, वहीं पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हर वर्ग को समान रूप से न्याय प्राप्त हो सके। इसके लिए उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने पर अगर विचार किया जाएगा, तो यह देश के बहुत बड़े हित में होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

4.00 P.M.

श्री ईश्वर सिंह (हरियाणा) : सर, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अन्दर एक ही उच्च न्यायालय था। यह सारा एक दुर्गम और पथरीला इलाका है। खास कर मणिपुर के अन्दर बर्फ पड़ती है, ठंडा एरिया है। वहाँ एक ही हाई कोर्ट में केस लेकर जाना पड़ता है। इससे आम आदमी को बहुत ज्यादा कठिनाई थी। जब त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के अन्दर अलग-अलग हाई कोर्ट बनने जा रहा है, तो मैं मंत्री जी का इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे अच्छे काम की शुरुआत की है, जिसकी सख्त जरूरत थी। सर, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने 22 जनवरी 2012 को 41वाँ स्थापना दिवस मनाया। इसमें मेघालय को 1971 में पूर्ण दर्जा मिला। तब से इसकी बहुत जरूरत थी। जैसा कहते हैं कि "न्याय आपके द्वार", इससे इसकी पूर्ति होती है।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) पीठासीन हुए]

सर, इसके साथ ही मैं यह चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने उच्च न्यायालय की शुरुआत की है, उसी प्रकार से मेघालय और असम में आईएएस कैडर के जो ऑफिसर्स हैं, जो मणिपुर और त्रिपुरा के साथ है, उस कैडर को अलग किया जाए। यह उनकी सबसे पहली डिमांड है।

सर, चूँकि मैं हरियाणा से आता हूँ, मैं मंत्री जी से यह निवेदन करता हूँ कि इसी तरह से पंजाब-हरियाणा के हाई कोर्ट का बहुत पुराना मसला है। हरियाणा का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसका अपना अलग स्थान है। पैदावार के हिसाब से हम पंजाब के बराबर चले गए हैं। वहाँ इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि वहाँ हजारों केसेज़ पेंडिंग हैं। इसलिए चंडीगढ़ के अन्दर जो हाई कोर्ट है, 60:40 के रेशियो से हरियाणा को उसी बिल्डिग में 40 परसेंट जगह दी जाए और हरियाणा के हाई कोर्ट को अलग किया जाए। यह मेरी डिमांड है। यह हमारा हक भी बनता है। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री जी इसको भी पूरा करेंगे। धन्यवाद।

SHRI P. CHIDAMBARAM : Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to S/Shri Bhubaneswar Kalita, Tarun Vijay, Shrimati Jharna Das Baidya, Sukhendu Sekhar Roy, Shrimati Vasanthi Stanley, Ram Kripal Yadav, Shantaram Naik, Narendra Kumar Kashyap and Ishwar Singh for the support that they have extended to this Bill.

Sir, I am glad that through this Bill, we have found some time to pay attention to the North-Eastern Region. The North-Eastern Region is usually at the periphery of our sight, and that itself is a reason that there is a sense of alienation among the people of the North-East.

Today, we are happy that we are able to establish High Courts in three States — Manipur, Meghalaya and Tripura. I am absolutely certain in my mind that the people of these States will be deeply grateful to the Parliament for making this law.

Sir, a number of issues were raised which go far beyond the scope of this law. Fortunately, the Minister of Law and Justice was present for most of the time, and I am sure, he has taken note of the issues raised by hon. Members. The most important issue is the delay in the delivery of justice.

As a person who practiced law for many years, I am deeply concerned about the grave delays in delivery of justice. We have 895 sanctioned posts of Judges in this

country, which is less than one High Court Judge for a million people. Even if you take the population of India as 1,200 million, we should have, at least, 1,200 High Court Judges whereas we only have a sanctioned strength of 895, out of which, 260 posts are vacant. So, roughly, 30 per cent of the sanctioned posts are vacant. In the Guwahati High Court, things are much better, where out of 24 sanctioned posts, only one is vacant but there are very large vacancies in other High Courts.

Sir, a couple of days ago, the Law Minister said in one of the Houses that he is in constant touch with the Chief Justice of India and the Chief Justices of the High Courts because the proposal for appointment of a Judge has to now emanate from the judiciary, from the collegium, and, not from the Government.

I think, it is important that all the vacancies are filled, more posts of Judges are created, and, qualified and eminent people are appointed as Judges. Sir, as far as the Benches are concerned, this again is a complex issue. There is always a demand for a Circuit Bench and Permanent Bench of a High Court in another city of the State. There are numerous demands for setting up Circuit Benches or Permanent Benches of the Supreme Court in different parts of India. But, obviously, these questions cannot be resolved in the short span of this debate. We have to carry the High Courts and the Supreme Court with us, and, I am sure that the Law Minister will address these issues.

Sir, the only question which, I think, I should answer is as to when will these High Courts begin to actually function. Actually, these courts are functioning in the sense that they are functioning as Benches of the Guwahati High Court. Judges are sitting today in Manipur, Tripura and Meghalaya, and, the Act says, "This Act shall come into force on such date as the Central Government may, by notification, appoint." We will appoint a date as soon as the President's Accent is received, and, under section 28(B), such of the Judges of the common High Court holding office immediately before the commencement of the North-Eastern Areas (Reorganisation) and Other Related Laws (Amendment) Act, 2012, that is, this Act, as may be determined by the President, after ascertaining their option, shall, on such commencement, cease to be the Judges of the common High Court, and, become a Judge of the High Court of Meghalaya or the High Court of Manipur or the High Court of Tripura, as the case may be. So, between now and the date of commencement, we will ascertain the option of the Judges and on the date of commencement, the Judge sitting in that High Court, because he has exercised the option, will become a Judge of that High Court and the High Court will begin to work as a High Court. So, there is no difficulty, provision is being made.

I am deeply grateful to all the hon. Members. I share the concern of my good friend, Mr. Shantaram Naik. I also share the concern of my friend, Mr. Ishwar Singh, regarding the Punjab and Haryana High Court. I think, these questions should be resolved and the way to resolve them is known. The solution is also known. I think, it

[SHRI P. CHIDAMBARAM]

only requires a little determination and obtaining the consent of the Chief Justices in order to resolve these issues. In my personal opinion, there is a great degree of legitimacy in the demand for a separate High Court for Goa and separate High Courts for Punjab and Haryana but this is a subject which the Law Minister should deal with. Thank you, Sir.

SHRI BHUBANESWAR KALITA : Sir, the hon. Minister has rightly said that there will be separate High Courts in Tripura, Meghalaya and Manipur and, at present, they have the Gauhati High Court Benches in Manipur, Meghalaya and Tripura. Separate High Courts are being constituted now. Infrastructure is ready. Those High Courts will function now. The Gauhati High Court Judges will be sitting there and they will have an option to carry on as the Judges of Gauhati High Court or Tripura High Court or Meghalaya High Court, as the Minister has said. But, Sir, Judges are already over-burdened in Gauhati High Court and they have to go to the other Benches also in Meghalaya, Manipur and Tripura. Now, if they give them option to continue with those Benches in Tripura, Manipur, Meghalaya, there will be shortage of Judges in Gauhati High Court. The Gauhati High Court Judges are already over-burdened. What can be the solution to that? Whether the Judges will be increased in Gauhati High Court or some more Judges will be appointed in those newly set up High Courts?

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, हमारे सदस्य, नरेन्द्र कश्यप जी ने इस विधेयक पर अपने विचार रखे। उन्होंने खास तौर से जब न्याय की बात की, तब मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में SC, ST और OBC का representation नाम मात्र है। जब हम न्याय की बात करते हैं, तब हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है, ताकि SC, ST और OBC का जो तबका सदियों से वंचित रहा है, उनको भी न्याय मिल सके?

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, answer to the question raised by Shri Kalita is that while some Judges of the common High Court will become Judges of each of the three High Courts, at the same time, the docket of the common High Court will also get reduced and cases also would be transferred to these three High Courts. If, after that, the workload of the common High Court requires more Judges, like I know, the workload of every High Court requires more Judges, I gave the numbers, there is a procedure to sanction more Judges and appoint more Judges. I am sure, that the Law Ministry, the Chief Justice of India and the Chief Justices of the High Courts will address this issue. But, as I said, the more important question is not to sanction more posts and look at the vacancies, the important issue is to fill the 260 vacancies that already exist. And, I think, if these 260 vacancies are filled immediately, that itself will bring a great degree of relief to the litigant public.

As far as the other issue is concerned, the policy of the Government is that all sections of the people, if there are adequate number of qualified and deserving persons,

they should become Judges. And, in fact, it is happening. As more and more lawyers and more and more Subordinate Court Judges are recruited or join the Bar from the OBCs, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, more and more of them will be elevated to the High Court. 1 know this is happening in many High courts. In many High Courts, a number of people elevated belong to the OBCs, belong to the Scheduled Castes. But since you can become a Judge of the High Court only if you are a Judge of a Subordinate Court or a lawyer, more and more people must join the legal profession, more and more people must become Judges of Subordinate Courts. Then we will find that the representation for the OBCs, Scheduled Castes and Scheduled Tribes automatically increases. But I entirely support the argument that the High Courts must represent the plurality of the States of India.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : The question is:

That the Bill further to amend the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and Other Related Laws, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 13 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Now, we shall take up Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

*Demand for issuing directions to nationalized and other commercial banks to provide educational loans to students of weaker sections without surety

SHRI S. THANGAVELU (Tamil Nadu) : Sir, I would like to bring to the notice of the Government that education loans meant for students of various technical and professional courses are not reaching students belonging to the weaker sections of the society. In 2009-10, Government had introduced a scheme for providing interest-subsidy on loans to students belonging to the weaker sections. The hon. Minister of Finance had also promised to set up a Credit Guarantee Fund to ensure better flow of credit to

---

* Laid on the Table.